केंद्रीय बजट विकास को गति देगा : प्रो साक्षी

आईआईएम में परिचर्चा

रांची | प्रमुख संवाददाता

आईआईएम रांची के अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर फॉर लीडरशिप, पॉलिसी एंड गवर्नेंस (एबीवीसीएलपीजी), सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ओर से मंगलवार को केंद्रीय बजट 2022-23 पर परिचर्चा का आयोजन किया गया।

आईआईएम रांची की प्रो साक्षी ने सत्र का संचालन किया। उन्होंने कहा कि यह बजट बुनियादी ढांचे के विकास से विकास को गति प्रदान करेगा। 2022-23 के बजट में प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों, विशेष रूप से राजमार्गों के पूंजीगत व्यय को बड़ा बढ़ावा मिला है। दूसरे, राज्यों के लिए बजट बढ़ाया गया है, जिससे आर्थिक परिवर्तन होगा। तीसरा, बजट में किसानों के लिए हाई-टेक सेवाओं, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और कृषि के लिए ड्रोन से लेकर डिजिटल नौकरियों और डिजिटल विश्वविद्यालयों, डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल मुद्रा और अंत में जलवायु पुनरुत्थान के लिए नागरिकों को उन्नत करने के लिए कई डिजिटल पहल का प्रस्ताव किया गया है। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की प्राध्यापिका डॉ मौसमी दास, व्यापार और वाणिज्य, नीति आयोग के प्रमुख डॉ बद्री नारायणन गोपालकृष्णन, आद्री पटना के डॉ सुधांशु कुमार और एनआईपीएफपी, नई दिल्ली की डॉ लेखा चक्रवर्ती ने बतौर वक्ता हिस्सा लिया।

विशिष्ट वक्ता डॉ बद्री नारायणन गोपालकृष्णन ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सेज को पूरी तरह से आईटी आधारित बनाया जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। सरकार सीमा शुल्क को कम करने में सुधार करेगी, जिससे निर्यात बढ़ेगा और सोने और हीरे पर आयात शुल्क कम होगा। इससे राजकोषीय बजट के अवमूल्यन को कम करने में मदद मिलेगी। एमएसएमई को बचाने के लिए टैक्स में कटौती की गई है। सरकार मिश्रित ईंधन के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया।

डॉ मौसमी दास ने अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया। कहा कि कुछ चुनौतियां बड़ी हैं। खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती असमानता, कम घरेलू निवेश, कृषि क्षेत्र में पिछड़ापन, जैसी चुनौतियां हैं। बजट का फोकस लघु अवधि से मध्यम/दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर स्थानांतरित हो गया।

राजस्व पर भरोसा कर आर्थिक सुधार को बढ़ावा

डॉ सुधांशु कुमार और डॉ लेखा चक्रवर्ती ने इस बात पर जोर दिया कि यह बजट सरकार को अपने वित्तीय स्थिरता उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक विकास और राजस्व पर भरोसा कर आर्थिक सुधार को बढ़ावा देता है। कहा कि यह राजकोषीय समेकन ऋण अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति की सुविधा प्रदान करेगा, जो भारत की रेटिंग पर नकारात्मक दृष्टिकोण को हल करेगा। उन्होंने आगे कहा कि चल रहे महामारी संकट के कारण करों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार की ओर से मान्यता, संकल्प और पुनर्पूंजीकरण सहित कई सुधार किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में गिरावट आई और बाद में लाभ में वृद्धि हुई।

Hindustan_23.02.2022_Pg. 04